अमर उजाला | लखनऊ | बुधवार | 22 मई 2013

उद्यमी सम्मेलन आज सीएम करेंगे उद्घाटन

लखनऊ (ब्यूरो)। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) बुधवार को उद्यमी महासम्मेलन 2013 का आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेगा। जो चार सत्र में संपन्न होगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुबह 11 बजे महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को प्रेसवार्ता में आईआईए प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर एवं प्रदेश महामंत्री मनीष गोयल ने संयुक्त रूप से दी।

आईआईए के आयोजन में प्रदेश से 800 उद्यमी जुटेंगे

सरकार ने औद्योगिक निवेश के लिए उद्योग बंधु को मजबूत करके और एंट्री टैक्स घटाकर उद्यमियों के प्रति सकारात्मक संकेत दिया है। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा राज्यमंत्री भगवत शरण गंगवार विशिष्ट अतिथि सहित उद्योग, विकास, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से जुड़े सचिव व सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की भी भागीदारी रहेगी। महासम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 800 उद्यमियों के जुटने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष रेट कांट्रेक्ट प्रक्रिया को दुबारा स्थापित करने, टैक्स की समस्या, औद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता की नीति को बढ़ाने, उद्यमियों के गृहकर की गणना अलग से करने, वैट की विसंगति को समाप्त करने और बिजली की समस्याओं को उठाएंगे। लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन प्रशांत भाटिया ने बताया कि उत्पादों की प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर से 800 से अधिक उद्यमी जुटेंगे।

डेली न्यूज़
लखनऊ, बुधवार, 22 मई 2013 3

उद्यमी महासम्मेलन आज, सीएम करेंगे उद्घाटन

- ब्यूरोक्रेट्स के चलते सरकार की नीतियां उद्यमियों तक नहीं पहुंच रहीं
- सपा सरकार की योजनाएं फाइलों में बंद कर रहे अधिकारी, उद्यमी परेशान
- औद्योगिक क्षेत्र के लिए गृहकर नीति अलग से बनाने की मांग
- प्रदेश के लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं घोषणाएं

लखनऊ (डीएनएन)। प्रदेश सरकार लघु उद्यमियों के लिए तमाम योजनाएं बना रही है। लगातार इसकी घोषणाएं भी की जा रही हैं। औद्योगिक नीतियों पर चर्चा कर प्रदेश सरकार लघु उद्यमियों को लाभ देने की बातें भी कई बार कर चुकी है। इसके बावजूद सत्ता में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स प्रदेश सरकार को बदनाम कर उसकी योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे। लघु उद्यमियों के लिए बनाई गई नीतियों को फाइलों में कैद कर बंद कर रहे हैं।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देश के सबसे बड़े उद्यमी महासम्मेलन के आयोजन से एक दिन पहले यह बात मंगलवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कही। आईआईए के अध्यक्ष चुगुल किशोर, महासचिव मनीष गोयल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमियों के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे। उनकी मांग है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए गृहकर नीतियां अलग से बनाई जाएं। प्रदेश में स्थित सभी लघु उद्योगों के पास जो जमीन होती है उसके एक हिस्से पर ही भवन और कारखाना होता है। जितने हिस्से में भवन और कारखाना हो, उसी हिस्से का गृहकर जमा कराया जाए। खाली भूभाग के लिए गृहकर उनसे जमा न कराया जाए। 14 प्रतिशत कर लगाने और वैट अधिक होने के कारण प्रदेश के तमाम लघु उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। प्रदेश की क्रय नीति अलग से बनाई जाए। जिससे लघु उद्यमियों के तैयार माल की खरीद हो सके। सपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। उनके लिए योजनाएं बनाकर उन्हें स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अपने वादे पूरे करने की कई बार घोषणाएं तो की हैं लेकिन किन्हीं कारणों से अभी भी उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। आज उद्योगों को लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किए जा रहे हैं, इससे उद्यमियों को कई तकनीकी समस्याएं पैदा होती हैं। लाइसेंस के लिए उद्यमियों से 10 वर्ष का एकमुश्त पैसा लेकर आजीवन के लिए जारी किए जाने की मांग भी की। लघु उद्योग को बढ़ावा देने और उद्यमियों को प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए। बिजली न मिलने के कारण लघु उद्योग चौपट हो रहे हैं। इससे पहले उद्यमी महासम्मेलन वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। उसके बाद प्रदेश में राजनीतिक सपोर्ट न मिलने के कारण यह सम्मेलन नहीं हो सका था। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के लघु उद्यमियों की समस्याओं को प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा। उद्यमी महासम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को सुबह 10 बजे करेंगे। मुख्यमंत्री के बाद सम्मेलन को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सचिव भारत सरकार एमएसएमई, विकास आयुक्त भारत सरकार, प्रमुख सचिव सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सहित तमाम लोग संबोधित करेंगे।

हिन्दुस्तान
लखनऊ • बुधवार • 22 मई 2013

सीएम के सामने आज मांगें रखेंगे लघु उद्यमी

राज्य मुख्यालय। प्रदेश के छोटे उद्यमी चाहते हैं कि सरकार प्रदेश में बनी वस्तुओं को खरीदने की नीति को बहाल करे। सरकारी खरीद में कर्रों को आसान बनाया जाए। औद्योगिक इकाइयों से गृह कर अलग से औद्योगिक श्रेणी बना कर लिया जाए। यही नहीं उद्यमी सपा के चुनावी घोषणा पत्र के उस वायदे की याद दिला रहे हैं जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक भूखंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदला जा सके।

लघु उद्यमियों की यह मांगे बुधवार को यहां होने वाले उत्तर प्रदेश उद्यमी महासम्मेलन में प्रदेश सरकार के सामने रखी जाएगी। 12 साल बाद हो रहे इस महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों उद्यमी शामिल होंगे। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगुल किशोर ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि वह लघु उद्यमियों की कई सालों से लंबित मांगों को पूरा कराएं। प्रदेश में ही बनी वस्तुओं की सरकारी खरीद की नीति पिछले साल खत्म हो गई। अब सरकारी अफसर इस आगे बरकरार रखने का विरोध कर रहे हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि लघु उद्योगों के लिए इस नीति को लाना बहुत जरूरी है। विसं

जनसंदेश टाइम्स
बुधवार, 22 मई 2013

दर अनुबंध प्रणाली फिर चालू करें : आइआइए

लखनऊ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग (एमएसएमई) चाहते हैं कि सरकारी विभागों द्वारा उनसे खरीदी जाने वाली सामग्री में उद्योग निदेशालय के स्तर पर केंद्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को फिर से चालू किया जाए। साथ ही आइआइए ने औद्योगिक इकाइयों के लिए भवन कर की अलग श्रेणी निर्धारित किये जाने की भी मांग की है।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) की ओर से बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किये जाने वाले उद्यमी महासम्मेलन में एमएसएमई की ओर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने यह मांगें रखी जाएंगी।

आइआइए के अध्यक्ष जुगल किशोर और महासचिव मनीष गोयल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री से प्रदेश में एमएसएमई से प्राथमिकता के आधार पर माल खरीदने के लिए निर्धारित क्रय वरीयता नीति की समयसीमा बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। अन्य राज्यों में वैट की कम दरों को देखते हुए आइआइए की मंशा है कि है राज्य सरकार उप्र. में जो माल खरीदे उसके मूल्य की गणना कर रहित हो। सरकारी खरीद का 20 प्रतिशत एमएसएमई से करने का मुद्दा भी महासम्मेलन में उठाया जाएगा। आइआइए औद्योगिक इकाइयों की जमीनों को लीज से फ्री होल्ड करने के सपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को अमल में लाने की मांग भी करेगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से तुलना के आधार पर वैट की दर को युक्तिसंगत बनाने का मुद्दा भी महासम्मेलन में उठाया जायेगा। इसमें खासतौर पर प्लांट व मशीनरी पर वैट की दर को 14.5 से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की जाएगी। दस साल का धन एकमुश्त जमा कर उद्यमियों को आजीवन लाइसेंस की सुविधा देने का मुद्दा भी आइआइए की मांगों में शामिल होगा। ब्यूरो

मांग

केंद्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली से होगा उद्यमियों को लाभ

पायनियर
लखनऊ, बुधवार, 22 मई, 2013

उप्र उद्यमी महासम्मेलन-2013 आज

छोटे उद्योगपति मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे अपनी समस्या

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में पिछली बसपा की सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) की खासी अंदेखी हुई। बड़े उद्योगपतियों के आगे सरकार ने (एमएसएमई) के साथ सौतेला व्यहार किया। यही कारण रहा कि बसपा सरकार में (एमएसएमई) कभी एक मंच पर नहीं आ पाए है। सत्तारुढ़ दल समाजवादी पार्टी की सरकार में काफी समय बाद ऐसा मौका आ रहा है जब करीब 2 हजार से ज्यादा छोटे उद्यमी प्रदेश के मुख्यमंत्री से रुबरु होकर अपनी मांगों और समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे।

पत्रकारों से बात करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के अध्यक्ष जुगल किशोर और महामंत्री मनीष गोयल ने कहा कि एमएसएमई चाहते हैं कि सरकारी विभागों द्वारा उनसे खरीदी जाने वाली सामग्री में उद्योग निदेशालय के स्तर पर केंद्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को फिर से चालू किया जाए। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भवन कर को अलग श्रेणी निर्धारित किये जाने की भी मांग की हैं। बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किये जाने वाले

एमएसएमई के साथ बसपा सरकार ने नहीं किया पूरा सहयोगः आईआईए

उद्यमी महासम्मेलन में उद्यमी अपनी कई मांगे प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रदेश में एमएसएमई से प्राथमिकता के आधार पर माल खरीदने के लिए निर्धारित क्रय वरीयता नीति की समयसीमा बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। अन्य राज्यों में वैट की कम दरों को देखते हुए आईआईए की मंशा है कि है राज्य सरकार उप्र. में जो माल खरीदे उसके मूल्य की गणना कर रहित हो।

सरकारी खरीद का 20 प्रतिशत एमएसएमई से करने का मुद्दा भी महास मेलन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन औद्योगिक इकाइयों की जमीनों को लीज से फ्री होल्ड करने के सपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को अमल में लाने की मांग भी करेगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से तुलना के आधार पर वैट की दर को युक्तिसंगत बनाने का मुद्दा भी महासम्मेलन में उठाया जायेगा।

स्वदेश चेतना

लखनऊ

बुधवार, 22 मई 2013

इण्डिा प्रतिबन्धन में उ० प्र० उद्यागि महासम्मेलन के बारे में प्रेस को अवगत कराते संजय कौल।
छाया : स्वदेश चेतना